NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में विनिवेश: राजकोषीय स्थिरता का मार्ग

भारत में विनिवेश: राजकोषीय स्थिरता का मार्ग

सन्दर्भ

- हाल के घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि भारत सरकार अपने विनिवेश अभियान की गति खो रही है, जिससे इसके दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

भारत में विनिवेश रणनीति के बारे में

- विनिवेश से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी स्वामित्व हिस्सेदारी बेचती है या उसका परिसमापन करती है।
- इसका उद्देश्य दक्षता को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और गैर-कर राजस्व उत्पन्न करना है।
- भारत में विनिवेश की शुरुआत 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान हुई थी, जिसका उद्देश्य राजकोषीय भार को कम करना और प्रबंधकीय दक्षता लाना था।
- इसका नेतृत्व वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है।
- DIPAM के अनुसार, इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - राजकोष पर राजकोषीय भार कम करना;
  - सार्वजनिक वित्त में सुधार;
  - सार्वजनिक उद्यमों में व्यापक शेयरधारिता को प्रोत्साहित करना;
  - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजी क्षेत्र की दक्षता लाना;
  - कम प्रदर्शन करने वाली परिसंपत्तियों से मूल्य अनलॉक करना;
- DIPAM, CPSEs में सरकारी इक्विटी का प्रबंधन करता है तथा शेयरों या परिसंपत्तियों की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

विनिवेश के प्रकार

- **अल्पसंख्यक विनिवेश:** सरकार नियंत्रण बरकरार रखती है।
- **बहुसंख्यक विनिवेश:** प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण।
- **रणनीतिक विनिवेश:** स्वामित्व और नियंत्रण का पूर्ण हस्तांतरण।

विनिवेश के प्रति बदलता दृष्टिकोण

- **नीति विकास:** 2021-22 के बजट में एक नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति पेश की गई, जिसमें CPSEs में न्यूनतम सरकारी उपस्थिति पर बल दिया गया।
  - इसने रणनीतिक क्षेत्रों में न्यूनतम उपस्थिति रखने का प्रस्ताव रखा।
  - गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में, CPSEs का या तो निजीकरण कर दिया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
- **मूल्य सृजन की ओर झुकाव:** अधिकारियों ने दोहराया है कि स्पष्ट विनिवेश लक्ष्यों के बजाय मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  - जीवंत इक्विटी बाजार के बावजूद सरकार 2024-25 में विनिवेश के माध्यम से केवल ₹10,000 करोड़ जुटाएगी।

- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि 2024-25 में इक्विटी बाजार में कुल धन उगाही ~3.7 ट्रिलियन से अधिक थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 90% अधिक थी।

विनिवेश में चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन अंतराल:** 2021 में डीपीई को वित्त मंत्रालय में एकीकृत करने के बावजूद, नई नीति पर प्रगति धीमी रही है।
  - विनिवेश को प्रायः एक सतत नीतिगत उद्देश्य के बजाय राजकोषीय घाटे को कम करने की आवश्यकता से प्रेरित किया जाता है।
- **राजनीतिक प्रतिरोध:** विनिवेश को विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसे प्रायः 'पारिवारिक संपत्ति बेचने' के रूप में चित्रित किया जाता है।
  - राजनीतिक आम सहमति के अभाव ने विनिवेश कार्यक्रमों के आक्रामक अनुसरण में बाधा उत्पन्न की है।
- **आर्थिक निहितार्थ:** कैग रिपोर्ट (2022) से पता चला है कि 198 सरकारी कंपनियों का संचित घाटा ₹2 ट्रिलियन से अधिक है, जिससे 88 कंपनियों की निवल संपत्ति कम हो गई है।
  - इन घाटे से राजकोष पर बोझ बढ़ रहा है, जिससे निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता रेखांकित होती है।
- **लचीलापन बनाम उपेक्षा:** हालाँकि स्पष्ट विनिवेश लक्ष्यों की अनुपस्थिति लचीलेपन की अनुमति देती है, लेकिन इससे इस महत्त्वपूर्ण राजस्व प्रवाह की उपेक्षा का खतरा रहता है।

प्रमुख सरकारी कदम

- **संबंधित विभागों का विलय:** केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय में दो विभागों - सार्वजनिक उद्यम विभाग और DIPAM - के विलय की प्रक्रिया में है। इसका उद्देश्य CPSEs की कार्यकुशलता और प्रदर्शन में सुधार लाना है।
- **केंद्रीय बजट (2021-22):** एक सार्वजनिक क्षेत्र नीति में कहा गया है कि सरकार CPSEs में अपनी उपस्थिति कम से कम करेगी।
  - इसने रणनीतिक क्षेत्रों में न्यूनतम उपस्थिति रखने का प्रस्ताव रखा। सामरिक क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, परिवहन, दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और बैंकिंग शामिल हैं।
  - गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में, CPSEs का या तो निजीकरण कर दिया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण पहल

- **निष्क्रिय परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण:** सरकार ने सीपीएसई की अधिशेष भूमि और अन्य गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन की शुरुआत की है।
  - इसका उद्देश्य निष्क्रिय परिसंपत्तियों का मूल्य बढ़ाना तथा अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना है।
- **राज्यों के लिए प्रोत्साहन:** सरकार ने राज्यों को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश हेतु प्रोत्साहित करने हेतु केंद्रीय निधियों के प्रोत्साहन पैकेज का प्रस्ताव किया है।
- **प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश और रणनीतिक बिक्री:** सरकार ने सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ, बिक्री के लिए प्रस्ताव और रणनीतिक बिक्री जैसे तरीकों का उपयोग किया है।
  - प्रमुख उदाहरणों में एयर इंडिया का निजीकरण और जीवन बीमा निगम का प्रस्तावित आईपीओ शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय निवेश कोष :** इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, जो विनिवेश से प्राप्त आय को विकास परियोजनाओं और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में लगाता है।

आगे की राह

- **लक्षित दृष्टिकोण:** सरकार को गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक कल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए।
- **हितधारक सहभागिता:** कर्मचारियों, यूनियनों और जनता के साथ पारदर्शी संचार चिंताओं को दूर करने और सामान्य सहमति बनाने में सहायता कर सकता है।
- **DIPAM को मजबूत बनाना:** DIPAM को प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए और विनिवेश योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

निष्कर्ष

- डीपीई और DIPAM का विलय, सीपीएसई के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- यद्यपि मूल्य सृजन पर ध्यान देना सराहनीय है, लेकिन आक्रामक विनिवेश कार्यक्रम के लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
- सीपीएसई के प्रबंधन और विनिवेश के बीच संतुलन हासिल करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, रणनीतिक योजना और कुशल कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी।

Source: BS

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: सरकार अपने विनिवेश लक्ष्यों को बाजार की अस्थिरता और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक हितों जैसी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता के साथ कैसे संतुलित कर सकती है?

■■■■